शुक्रवार, 14 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में गॉल पहुंच चुकी

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राजकुमार राव की 'प्रहार' की नई रिलीज डेट का ऐलान

Page-05

₹50 हजार की योजना

यूपी चुनाव से पहले महिलाओं पर फोकस अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना

- योजना के तहत चुनाव से पहले महिलाओं को 20 हजार रुपये की पहली किस्त देने का प्रस्ताव है।
- सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार जनता के आक्रोश से डरी हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बड़ी योजना पर विचार कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की चर्चा है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी योजना का अंतिम प्रारूप या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।सूत्रों के मुताबिक, योजना के तहत चुनाव से पहले महिलाओं को 20 हजार रुपये की पहली किस्त देने का प्रस्ताव है। इसके बाद अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो 10-10 हजार रुपये की तीन और किस्तें दिए जाने की संभावना है। इस तरह लाभार्थियों को कुल 50 हजार रुपये की सहायता मिल सकती है।सरकार के स्तर पर प्रस्तावित योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद देने के साथ-साथ स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि योजना को महिला कल्याण विभाग के जरिए लागू किया जा सकता है। हालांकि, पात्रता, भुगतान की समयसीमा, लाभार्थियों की संख्या और योजना के क्रियान्वयन को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है।उत्तर प्रदेश की इस प्रस्तावित योजना की तुलना बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए लागू की गई आर्थिक सहायता योजनाओं से भी की जा रही है। इन राज्यों में चुनावों के दौरान महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली योजनाएं राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रही हैं।योजना को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए अब पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछले 10 वर्षों में महिलाओं को उनका हक देने के बजाय अब चुनाव से पहले 20 हजार रुपये देने का वादा कर रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगर महिलाओं को सालाना 50 हजार रुपये दिए जाते तो पिछले 10 वर्षों में उन्हें 5 लाख रुपये मिल सकते थे। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार की कथित विफलताओं से जोड़ते हुए कहा कि अब चुनाव से पहले सिर्फ 20 हजार रुपये देने की बात की जा रही है।

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला

बोले- छात्रों को अपनी बात रखने से रोका गया

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने NEET-UG पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। नई दिल्ली में आयोजित 'रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन' में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय व्यवस्था और नियंत्रण के नाम पर उन्हें अपनी बात रखने से रोक रही है।राहुल गांधी ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र परेशान थे और अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा देश में ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहती है, जिससे कुछ खास लोगों को फायदा मिले। इसके विपरीत कांग्रेस का उद्देश्य लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देना है।अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने एक रेप पीड़िता के परिवार से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन व्यवस्था के नाम पर उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। राहुल ने इसी उदाहरण के जरिए आरोप लगाया कि सरकार अक्सर अव्यवस्था का हवाला देकर लोगों की आवाज को रोकने का प्रयास करती है।NEET विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर हुआ विरोध प्रदर्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हुआ। वहीं, संसद में विपक्षी दल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करते रहे हैं।

हरभजन सिंह का खुलासा

AAP छोड़ने पर बोले- पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी (AAP) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के फैसले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। उन्होंने कहा कि AAP में उनके सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया गया और जिस उद्देश्य से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, वह पूरा नहीं हो रहा था। इसी निराशा के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पीटीआई के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में 46 वर्षीय हरभजन ने कहा कि 2022 में जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें AAP में शामिल होने के लिए कहा था, तब उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि राज्यसभा के माध्यम से खेलों के विकास से जुड़े मुद्दे उठाना था। उन्होंने कहा, "मैंने उस समय साफ कर दिया था कि मैं सिर्फ खेलों की बात करूंगा और राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरा काम नहीं है।" हरभजन के मुताबिक, उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए, लेकिन पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा, "जब मैंने अपने विचार सामने रखने की कोशिश की, तो पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई। मेरे विचार सिर्फ विचार बनकर रह गए।" उन्होंने कहा कि अगर उनके सुझावों की दिशा में छोटा-सा कदम भी उठाया जाता तो वह पार्टी नहीं छोड़ते। लेकिन जिस काम के लिए उन्होंने AAP का साथ दिया था, वही पूरा नहीं हो रहा था। AAP छोड़ने के बाद पार्टी की ओर से उन्हें और अन्य नेताओं को 'विश्वासघाती' बताया गया था। इस दौरान जालंधर स्थित हरभजन के घर के बाहर प्रदर्शन भी हुए और उनका पुतला जलाया गया। इन प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए हरभजन ने कहा कि वह प्रदर्शनकारियों के नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि सभी जानते हैं कि वे कौन थे और कहां से आए थे।

भोजपुर एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला

भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी

बिहार के भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 28 वर्षीय भरत तिवारी के परिवार को राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को घोषणा की कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। यह फैसला न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।भरत तिवारी की 17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक, टीम जब तिवारी को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने अवैध हथियार से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई, जिसमें तिवारी घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।हालांकि, भरत तिवारी के परिवार ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप था कि तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और अपना हथियार भी फेंक दिया था। सोशल मीडिया पर सामने आए एक कथित वीडियो को लेकर भी दावा किया गया कि उसमें मुठभेड़ से कुछ समय पहले तिवारी को हथियार फेंकते हुए देखा जा सकता है।घटना के बाद इलाके में काफी आक्रोश देखने को मिला था। परिवार और स्थानीय लोगों ने भरत तिवारी को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वह सरकारी अधिकारियों के सामने लोगों की समस्याएं और स्थानीय मुद्दे उठाता था। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी तेज हो गई थी।विवाद बढ़ने के बाद बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। इसी मामले में हाल ही में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के कॉन्स्टेबल अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है।

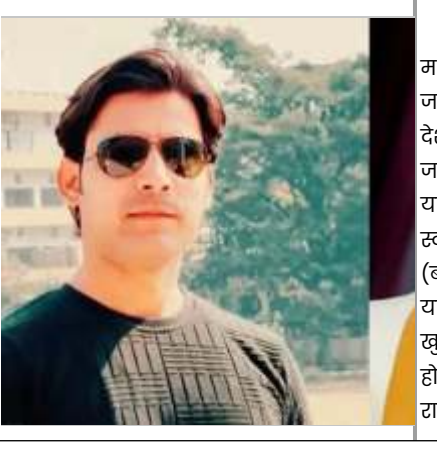

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जल्द लागू की जाएगी

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जल्द लागू की जाएगी और इसके साथ ही राज्य देश के उन प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जहां यह कानून लागू है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। यादव स्वतंत्रता दिवस के पहले भोपाल के भोजताल (बडा तालाब) में नौकाओं पर आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे खुशी है कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। इससे मध्य प्रदेश देश के उन प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जहां यूसीसी लागू है और राज्य में समानता की पवित्र भावना मजबूत होगी।" उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और हिंदू, मुस्लिम, पारसी या ईसाई, सभी पर समान कानून लागू होंगे। बड़ा तालाब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध बोट क्लब देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा। एक अधिकारी ने बताया कि देश में पहली बार झील के बीचोंबीच तैरता हुआ तिरंगा भी बनाया गया।

सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला

नांदेड़ साहिब में चाकू से वार की कोशिश; पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को हमला किए जाने से हड़कंप मच गया। तख्त श्री हजूर साहिब के पास माता साहिब गुरुद्वारे के नजदीक हुई इस घटना में एक हमलावर ने धारदार हथियार से बादल पर वार करने की कोशिश की। हमले में उनके हाथ पर चोट आई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया।जानकारी के मुताबिक, घटना सुबह करीब 11:30 बजे की है। सुखबीर सिंह बादल गुरुद्वारे की ओर जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और अचानक उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए हमलावर को रोक लिया। हालांकि, इस दौरान बादल को चोट लग गई। घटना में एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की जानकारी सामने आई है।हमले के तुरंत बाद पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, घटना गुरुद्वारे के परिसर के अंदर हुई, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद गुरुद्वारा परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई और व्यक्ति भी मौजूद था। पुलिस हमले के कारणों और आरोपी की पृष्ठभूमि की भी जांच कर रही है।सुखबीर सिंह बादल पंजाब की राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। वह शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं। ऐसे में धार्मिक स्थल पर उनके ऊपर हुए हमले ने राजनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर चिंता बढ़ा दी है।फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ के बाद ही हमले के पीछे की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।

हॉर्मुज पर अमेरिका-ईरान आमने-सामने नाकाबंदी के बीच 59 जहाजों का बदला रास्ता

हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब समुद्री आवाजाही और तेल सप्लाई पर असर डाल रहा है।अमेरिका की नाकाबंदी के बीच कई व्यावसायिक जहाजों के रास्ते बदले गए, जबकि ईरान अपने रुख पर कायम है।बढ़ते तनाव ने खाड़ी क्षेत्र में बड़े समुद्री टकराव और वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ा दिया है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

र्मुज पर अमेरिका और ईरान के दावों की जंग अब समुद्री जहाजों और तेल की सप्लाई तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच दर्जनों व्यावसायिक जहाजों का रास्ता बदला गया है, वहीं ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर, इजरायल की गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव को और पेचीदा कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी अब महज राजनीतिक दावे तक सीमित नहीं रह गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका इस रणनीतिक जलमार्ग पर 'टोटल कंट्रोल' रखता है और आने वाले समय में इसे अपने प्रभाव में बनाए रखने की योजना है। इसके उलट ईरान का कहना है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होतीं, हॉर्मुज को खोलने का सवाल ही नहीं उठता। यानी एक ही समुद्री रास्ते को लेकर दोनों देशों की कहानी बिल्कुल अलग है। वॉशिंगटन इसे अपने सैन्य प्रभाव और नौवहन नियंत्रण के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि तेहरान इसे अपनी रणनीतिक ताकत और दबाव बनाने के हथियार के रूप में देख रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, ईरान के खिलाफ दोबारा लागू की गई नौसैनिक नाकाबंदी के तहत अमेरिकी बलों ने 59 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला, तीन जहाजों को निष्क्रिय किया और दो को बोर्ड कर जांच की। यह घटनाक्रम बताता है कि हॉर्मुज का विवाद अब केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि समुद्री आवाजाही को सीधे प्रभावित करने लगा है। रिपोर्टों के मुताबिक एक ऐसे जहाज पर अमेरिकी हेलिकॉप्टर ने भी कार्रवाई की, जिसने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की थी। इस तरह की घटनाएं किसी बड़ी समुद्री भिड़ंत का खतरा बढ़ाती हैं, क्योंकि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज अलग-अलग देशों के झंडे लेकर चलते हैं। व्हाइट हाउस से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकाबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर बेहद गंभीर दबाव डाला है। अमेरिकी प्रशासन का संकेत है कि आने वाले महीनों में तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके पास कई विकल्प मौजूद हैं।व्हाइट हाउस से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकाबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर बेहद गंभीर दबाव डाला है। अमेरिकी प्रशासन का संकेत है कि आने वाले महीनों में तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके पास कई विकल्प मौजूद हैं। व्हाइट हाउस से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकाबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर बेहद गंभीर दबाव डाला है। अमेरिकी प्रशासन का संकेत है कि आने वाले महीनों में तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके पास कई विकल्प मौजूद हैं। लेकिन आर्थिक दबाव के बावजूद ईरान ने अपने रुख में नरमी का संकेत नहीं दिया है। तेहरान का संदेश साफ है कि हॉर्मुज को लेकर वह अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।

Meta ने हटाए 7.5 लाख से ज्यादा Minor Accounts, रेगुलेटरी दबाव बढ़ा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा ने गुरुवार को कहा कि उसने 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई लोगों के 7,50,000 से ज़्यादा अकाउंट्स को हटा दिया है। कंपनी ने यह कदम किशोरों के अकाउंट्स पर दुनिया के पहले बैन के बाद उठाया है और रेगुलेटरी दखल की संभावना को देखते हुए और कार्रवाई करने का वादा किया है। कंपनी ने बताया कि उसने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन लागू होने से ठीक पहले से लेकर जून तक 4,62,000 संदिग्ध इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 2,94,000 संदिग्ध फेसबुक अकाउंट्स को डीएक्टिवेट किया है।जनवरी तक हटाए गए अकाउंट्स की संख्या 3,31,000 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 1,73,000 फेसबुक अकाउंट्स थी। कंपनी ने कहा है कि वह उस कानून का पालन करना चाहती है जिसका उसने और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स ने खुलकर विरोध किया था। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेट रेगुलेटर उन प्लेटफ़ॉर्म्स (जिनमें मेटा के मालिकाना हक वाले प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं) के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, जिन पर कानून का पालन करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप है। किसी भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म ने मेटा द्वारा बताई गई समय-सीमा से मेल खाने वाला कंप्लायंस डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार के आंकड़ों और कई स्वतंत्र अध्ययनों से पता चला है कि बैन के शुरुआती तीन महीनों में भी 16 साल से कम उम्र के 10 में से 8 से ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया पर मौजूद थे।

कर्नाटक विधानसभा परिसर में मौजूद सरकारी कैंटीन कॉकरोच खाने की प्लेट्स पर घूम रहे

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कर्नाटक विधानसभा परिसर में मौजूद सरकारी कैंटीन को लेकर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जांच के दौरान कैंटीन में अस्वच्छ और अनहाइजीनिक स्थिति पाई गई। यहां बड़ी संख्या में कॉकरोच घूमते हुए मिले। ये कॉकरोच खाने की प्लेट्स पर घूम रहे थे। जानकारी के मुताबिक, विकास सौधा में मौजूद सरकारी कैंटीन का भी खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। विकास सौधा में कई मंत्रियों और वरिष्ठ I A S अधिकारियों के कार्यालय हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भी यहां स्थित कैंटीन में भोजन करते हैं। जांच के दौरान कैंटीन में रखी खाने की प्लेटों पर कॉकरोच दौड़ते हुए दिखाई दिए। बड़ी संख्या में कॉकरोच मिलने से कैंटीन की साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने कैंटीन की स्थिति का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आगे की कार्रवाई और जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद कैंटीन प्रबंधन के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं, यह स्पष्ट होगा। कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा प्रभाग की टीम ने बुधवार को होटल, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण फिर शुरू किया। टीम ने यहां विभाग के मुख्यालय स्थित कैंटीन का भी निरीक्षण किया, जहां उपयोग की अंतिम तिथि पार कर चुके खाद्य पदार्थ जब्त किए गए और स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया। खाद्य सुरक्षा प्रभाग की टीम ने विधान सौध, विधायकों के आवास और एमएस बिल्डिंग परिसर में स्थित होटलों तथा खाद्य कारोबार से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। मागड़ी रोड स्थित आरोग्य सौध कैंटीन की रसोई में इडली रवा और नारियल पाउडर जैसे उपयोग की अंतिम तिथि पार कर चुके खाद्य उत्पाद मिले। अधिकारियों के अनुसार, खाद्य उत्पादों का FSSAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार भंडारण भी नहीं किया गया था।

क्लैक्टन उपचुनाव के दौरान एक अनोखा उम्मीदवार लोगों का ध्यान खींच रहा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

ब्रिटेन में क्लैक्टन उपचुनाव के दौरान एक अनोखा उम्मीदवार लोगों का ध्यान खींच रहा है। काउंट बिनफेस नाम का यह उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान कूड़ेदान जैसी पोशाक पहनता है और खुद को एलियन बताता है। वह रिफॉर्म यूके के कट्टरपंथी नेता नाइजेल फराज के खिलाफ चुनाव मैदान में है। काउंट बिनफेस का असली नाम जॉन हार्वे है। 46 वर्षीय हार्वे लेखक और कॉमेडियन हैं। वे पहले भी कई चुनावों में अलग-अलग मजाकिया नामों से उम्मीदवार रह चुके हैं। 2017 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा मे के खिलाफ 'लॉर्ड बकेटहेड' नाम से चुनाव लड़ा था। बाद में कॉपीराइट विवाद के कारण उन्हें यह नाम छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 2018 में 'काउंट बिनफेस' नाम का नया किरदार बनाया। काउंट बिनफेस का नाम भी मजाकिया है। 'काउंट' राजशाही की एक उपाधि है, जबकि 'बिन' का मतलब कूड़ेदान होता है। यानी इसका मोटा-मोटी मतलब 'कूड़ेदान के चेहरे वाला काउंट' है। जॉन हार्वे 2019 में बोरिस जॉनसन के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा वे लंदन मेयर चुनाव और दूसरे उपचुनावों में भी किस्मत आजमा चुके हैं। काउंट बिनफेस के चुनावी वादे भी उनके अंदाज की तरह अलग हैं। वे कहते हैं कि जीतने पर कम से कम एक सस्ता घर जरूर बनवाएंगे। उनका एक और वादा है कि वे 'आपका टैक्स कम और बाकी सभी का टैक्स बढ़ाएंगे।' वे मशहूर गायिका एडेल को सरकारी संपत्ति घोषित करने की बात भी मजाकिया अंदाज में कहते हैं। क्लैक्टन सीट पर नाइजेल फराज मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालिया सर्वे में उन्हें करीब 73% वोट मिलने का अनुमान है। बड़ी पार्टियों लेबर, कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारे हैं।

बांग्लादेश में गहराया ऊर्जा संकट, रात 8 बजे बंद होंगे बाजार-शॉपिंग मॉल

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

बांग्लादेश का उर्जा संकट गहराता जा रहा है। बांग्लादेश अपने नागरिकों को जरूरी बिजली देने में नाकाम हो रहा है। बिजली की कमी से निपटने के लिए बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने शॉपिंग मॉल और दुकानों को रात 8 बजे बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद के भारत से अतिरिक्त डीजल सप्लाई की मांग करने के बाद ये नए कदम उठाए गए हैं। ऐसे में मदद के लिए ढाका की नजर दिल्ली की ओर लगी है। बांग्लादेश सरकार ने 12 अगस्त को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि शॉपिंग मॉल, बाजीर और दुकानें सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ही खुल सकती हैं। यह देश में चल रहे ऊर्जा संकट को दिखाता है। सरकार ने बाजार और मॉल के लिए नौ घंटे का समय तय किया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि सभी रोशन वाले बिलबोर्ड शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाने चाहिए। इसके अलावा सभी तरह की सजावटी या रोशन वाली लाइटें भी बंद रहेंगी। इसका मकसद आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल कम करना है। रिहायशी इलाकों में लंबी बिजली कटौती को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बांग्लादेश में ऊर्जा संकट इतना गंभीर है कि यह आदेश सिर्फ देश की राजधानी ढाका तक सीमित नहीं है। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे और आने वाले मेलों, ट्रेड फेयर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद के बीच हुई बैठक में महमूद ने भारत से और डीजल सप्लाई की मांग की थी। यह मांग बिजली और गैस की चल रही कमी से निपटने के लिए की गई थी, जिसने बिजली उत्पादन पर असर डाला है। इससे देश के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती बढ़ी है।

ढाका की मांग के बाद यह सवाल है कि क्या भारत की ओर से बांग्लादेश की मदद की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ा निर्यातक है, खासकर हमारे पड़ोसी देशों के लिए। हमें बांग्लादेश सरकार से डीजल की आपूर्ति का अनुरोध मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है।'

संपादक की कलम से

संसद लोकतंत्र का वह मंच है, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस, सवाल और जवाब के जरिए रास्ता निकाला जाता है। लेकिन जब संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा और गतिरोध बना रहे, तो इसका सीधा असर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर पड़ता है। मौजूदा स्थिति भी इसी चिंता को सामने रखती है। विपक्ष CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 20 जुलाई को हुई कथित पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े आरोपों पर चर्चा तथा सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि महत्वपूर्ण विधेयकों को हंगामे के बीच नहीं, बल्कि विस्तृत चर्चा के बाद आगे बढ़ाया जाना चाहिए।विपक्ष की यह मांग पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती कि जिन घटनाओं को लेकर देश में सवाल उठ रहे हैं, उन पर सरकार सदन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करे। खासकर जब किसी प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई या सार्वजनिक धन और धार्मिक संस्थानों से जुड़े गंभीर आरोपों की बात हो, तब पारदर्शिता और तथ्य सामने रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह सवाल उठाने के साथ-साथ सदन को चलाने में सहयोग करे।संसद में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार के पास बहुमत है, इसलिए विधेयकों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन बहुमत का अर्थ यह नहीं कि विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज किया जाए। दूसरी ओर, विपक्ष का काम सरकार को घेरना और जवाब मांगना है, लेकिन लगातार नारेबाजी और कार्यवाही बाधित करना लोकतांत्रिक बहस का विकल्प नहीं हो सकता।संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी नेताओं के बीच बातचीत के बावजूद अगर गतिरोध समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो यह दोनों पक्षों के लिए आत्ममंथन का विषय है। बातचीत केवल औपचारिकता न रहकर समाधान तक पहुंचनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह जिन मुद्दों पर विपक्ष जवाब मांग रहा है, उन पर तथ्य सदन के पटल पर रखे और विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चर्चा के दौरान उसे पर्याप्त अवसर मिले।लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन असहमति को संवाद में बदलना ही संसदीय परंपरा की असली परीक्षा है। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को संसद में बहस करने, कानून बनाने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भेजा है। इसलिए जरूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर संसद की गरिमा और जनता के हित को प्राथमिकता दें।संसद का समय बेहद मूल्यवान है। हर स्थगित कार्यवाही के साथ केवल राजनीतिक संदेश नहीं जाता, बल्कि जनता के सवालों पर चर्चा का अवसर भी खत्म होता है। इसलिए अब जरूरत हंगामे को और लंबा खींचने की नहीं, बल्कि जवाब, तथ्य और सार्थक बहस के जरिए गतिरोध खत्म करने की है। यही लोकतंत्र की मजबूती और संसद की गरिमा दोनों के लिए बेहतर रास्ता है।

मानसून सत्र वॉशआउट, विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते संसद की कार्यवाही लगातार बाधित रही।सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा जारी रहा और लोकसभा-राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया, वहीं सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

संसद का मानसून सत्र पूरी तरह से वॉशआउट हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र कई राजनीतिक टकरावों का गवाह बना। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। सत्र की समाप्ति पर लोकसभा अध्यक्ष ने परंपरा के मुताबिक, चाय पार्टी यानि TEA पार्टी का आयोजन किया। इससे जुड़ी बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की चाय पार्टी का बॉयकॉट किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद स्पीकर की टी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। विपक्ष की ओर से DMK के सिर्फ एक सांसद स्पीकर की चाय पार्टी में शामिल हुए हैं। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन भी संसद में गतिरोध नहीं टूटा। इससे पहले केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विपक्ष के बात करने और चर्चा करवाने की अपील की थी। शाह ने कहा था कि वो चर्चा बाद हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था अमित शाह के भाषण में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। एक तरफ जहां लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। वहीं, राज्यसभा की कार्रवाई में आज खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया गया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ मानसून सत्र समाप्त हो गया। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसदीय सत्र में 12 बिल पास हुए। लोकसभा में सिर्फ 19 फीसदी काम हुआ। लोकसभा में सिर्फ 1 दिन ही चर्चा हो पाई, नए सासंदों को अच्छी चर्चा का मौका नहीं मिला। लोकसभा में विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी और चर्चा से भागने के लिए बहाने बनाए। विपक्षी सांसद सिर्फ नारेबाजी के लिए संसद आए। संसदीय लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी का कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार किया। स्पीकर की क्लोजिंग स्पीच ना देने से विपक्षी दल नाराज हैं। DMK के सिर्फ एक सांसद स्पीकर की चाय पार्टी में शामिल हुए। राज्यसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। राज्यसभा में कार्यवाही जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुद्धकरण का मुद्दा उठाया। खरगे ने कहा कि उत्तराखंड में मेरे भाषण के बाद मैदान का शुद्धिकरण किया गया। वहीं, इस पर जेपी नड्डा ने कहा, हलद्वानी में जो हुआ वो दुखद है। शुद्धिकरण मामले की सरकार जांच कराएगी। खरगे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग थे। इस पर जेपी नड्डा ने कहा है बीजेपी के लोग नहीं थे लेकिन हम जांच करेंगे। जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया वो किस पार्टी या संगठन से संबंध थे, जिन्होंने किया था उनसे बात भी करिए।

गोगोई का अमित शाह पर हमला, बोले- सत्र खत्म होने से दो दिन पहले कुंभकर्ण की नींद से जागे

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 13 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की क्योंकि वे संसद के मॉनसून सत्र के ज़्यादातर समय मौजूद नहीं थे। गोगोई ने कहा कि शाह सत्र खत्म होने से सिर्फ़ दो दिन पहले ही अपनी 'कुंभकर्ण जैसी नींद' से जागे। गोगोई ने सवाल उठाया कि शाह ने असल बहसों में हिस्सा क्यों नहीं लिया, खासकर तब जब विपक्ष जंतर-मंतर पर 20 जुलाई की रैली के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर उनका बयान चाहता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गोगोई ने कहा कि गृह मंत्री 15 दिनों तक गायब रहे और सत्र खत्म होने से दो दिन पहले अपनी 'कुंभकर्ण जैसी नींद' से जागे, यह दावा करते हुए कि वह चर्चा के लिए तैयार हैं। जब असल चर्चा हो रही थी, तब आप कहाँ थे? सभी लोग अपनी राय दे चुके थे; बस आपके बयान का समय था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह और बातचीत की बात इसलिए कर रही है ताकि गृह मंत्री को विपक्ष की मांगों का जवाब देने से रोका जा सके। गोगोई ने कहा कि लेकिन उन्होंने बयान देने से टाल-मटोल की और बार-बार और बातचीत की मांग की - यह सिर्फ़ सदन से दूर रहने और अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने का बहाना था। आख़िरकार, जब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो रही थी, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहाँ पहुँचे; उन्होंने स्पीकर का संबोधन तक नहीं सुना। गोगोई ने यह भी दावा किया कि मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार डरी और सहमी हुई थी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह संसदीय कार्यवाही से पूरी तरह नदारद और दूर रहे। उन्होंने कहा कि हमने कई सत्र देखे हैं, लेकिन किसी भी सत्र में सत्ताधारी सरकार को इतना डरा और सहमा हुआ कभी नहीं देखा, जितना इस बार देखा है। शायद यह पहला ऐसा सत्र है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्यवाही से पूरी तरह नदारद और दूर रहे। गोगोई के मुताबिक, सरकार पूरे सेशन के दौरान बैकफुट पर रही और इन मुद्दों से बचना चाहती थी, ऐसा लग रहा था कि वह सदन से भाग रही है। गोगोई की ये बातें 12 अगस्त को अमित शाह के उस बयान के बाद आईं, जिसमें उन्होंने NEET पेपर लीक से जुड़े छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर संसद में सभी सवालों के जवाब देने के लिए अपनी तैयारी जताई थी। शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कहा कि वे चर्चा के लिए समय तय करने के लिए विपक्ष से बातचीत करें। स्पीकर को लिखे एक पत्र में शाह ने बताया कि पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पर सेशन के दौरान पहले ही चर्चा हो चुकी थी और उस समय विपक्ष के किसी भी सदस्य ने NEET परीक्षा का मुद्दा नहीं उठाया था। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी, सरकार इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा करने के लिए तैयार है।

राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी कथित आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 17 अगस्त को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका के साथ एक अलग ट्रांसफर पेटिशन भी दायर की है। दरअसल, मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को राहुल गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच और सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में अधिक संपत्ति है और इस मामले में जांच की जरूरत है। पिछले महीने हाईकोर्ट ने CBI को जांच की स्थिति बताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। CBI की ओर से दाखिल जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को एक आदेश दिया था, जिसमें कहा कि जांच एजेंसी का जवाब पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है और अदालत जांच की प्रगति को समझने की स्थिति में भी नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ED ने आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि जांच के दौरान कार्रवाई योग्य सामग्री सामने आती है तो वह आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। मामले को अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया था। अब राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी से जुड़ा एक अलग मामला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। इसमें एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास भारतीय पासपोर्ट के अलावा ब्रिटिश पासपोर्ट भी रहा है और इससे नागरिकता कानूनों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट ने शुरुआत में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में न्यायाधीश ने उस आदेश पर रोक लगा दी और मामले से खुद को अलग (recuse) कर लिया। यह घटनाक्रम शिशिर की ओर से मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए जाने के बाद हुआ था। यह मामला भी फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है।

शिक्षा विभाग ने बदला टाइम टेबल
बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ-डे

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई यानी हाफ-डे व्यवस्था फिर से लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से नया आदेश जारी कर दिया गया है। नए टाइम टेबल के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल अपने निर्धारित समय के अनुसार संचालित होंगे, जबकि शनिवार को दोपहर के बाद विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी जाएगी।शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालन के समय में आंशिक संशोधन करते हुए यह व्यवस्था लागू की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सञ्जन आर. के हस्ताक्षर से जारी निर्देश के मुताबिक राज्य के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को हाफ-डे रहेगा। विभाग ने पहले जारी 12 दिसंबर 2025 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया टाइम टेबल लागू किया है। इसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई के घंटों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के साथ शनिवार को विद्यार्थियों के लिए निर्धारित विशेष गतिविधियों को भी सुचारू रूप से संचालित करना है।नए आदेश के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। वहीं, शनिवार को स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। यानी सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस पर विद्यार्थियों को सामान्य दिनों की तुलना में कम समय स्कूल में रहना होगा।कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए शनिवार की व्यवस्था में विशेष प्रावधान किया गया है। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शनिवार को दोपहर 12 बजे तक पठन-पाठन और निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12:40 बजे तक बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी मिड-डे मील दिया जाएगा। भोजन समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी जाएगी। इससे छोटे बच्चों को शनिवार को स्कूल में कम समय बिताना पड़ेगा।हालांकि, स्कूल की छुट्टी होने के साथ शिक्षकों की जिम्मेदारियां पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को भी निर्धारित किया है। आदेश के अनुसार शिक्षकों को प्रतिदिन एक घंटे का समय इन अतिरिक्त कार्यों के लिए देना होगा। इस दौरान उन्हें अगले दिन और अगले सप्ताह की पाठ योजना तैयार करने, विद्यार्थियों के मूल्यांकन से संबंधित कार्य पूरे करने, प्रयोगशाला के प्रबंधन और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने जैसे काम करने होंगे।शिक्षा विभाग का यह बदलाव स्कूलों में पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शनिवार को कम समय में पठन-पाठन के साथ अन्य निर्धारित गतिविधियां पूरी कराने और फिर विद्यार्थियों को छुट्टी देने की व्यवस्था की गई है।नई व्यवस्था से जहां विद्यार्थियों, खासकर छोटे बच्चों को शनिवार को राहत मिलेगी, वहीं शिक्षकों को अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की योजना बनाने के लिए निर्धारित समय का इस्तेमाल करना होगा। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी संशोधित टाइम टेबल के अनुसार संचालन करना होगा।

पंजाब में MBBS छात्रों पर नई शर्त, पढ़ाई के बाद 2 साल सरकारी सेवा जरूरी

नीट काउंसलिंग 2026 शुरू होने के बाद मेडिकल दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई को लेकर राज्यों में बदलाव होते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए नई बॉन्ड पॉलिसी लागू की है। इसके तहत एकेडमिक ईयर 2025-26 से दाखिला लेने वाले छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य सेवाएं देनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 20 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। इस नए सिस्टम लागू होने के साथ ही ट्यूशन फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फरीदकोट सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग आयोजित करेगी। पंजाब में सरकारी कोटा, मैनेजमेंट कोटा, NRI या माइनॉरिटी कोटा और हर सीट NEET मेरिट के आधार पर भरी जाती है। पंजाब में मेडिकल एडमिशन नई पॉलिसी लागू की गई है। admission.bfuhsonline.ac.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब MBBS में एडमिशन लेने वाले छात्रों की डिग्री पूरी होने के बाद 2 साल तक सरकारी संस्थानों सेवाओं में सेवा देनी होगी। हालांकि, ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत दाखिला लेने वालों छात्रों के लिए यह अवधि 1 साल तय की गई है। बॉन्ड के तहत सेवा पंजाब सरकार के उन सरकारी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों या अन्य स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में दी जाएगी, जिन्हें सरकार समय-समय पर तय करेगी।

मिशेल स्टार्क ने 434 टेस्ट विकेट लेकर इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल बाएं हाथ के गेंदबाज का कीर्तिमान बनाया

भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में गॉल पहुंच चुकी

शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया इस वक्त श्रीलंका में है। भारतीय टीम यहां से सीधे कोलंबो पहुंची थी, जहां तीन दिन का एक वॉर्मअप मैच खेला गया था। टीम ने इस मैच को जीता भी था। अब असली टेस्ट की बारी है। जो गॉल में खेला जाएगा। इसके लिए टीम अब गॉल पहुंच चुकी है। इस दौरान भारतीय प्लेयर्स का शानदार स्वागत हुआ। उनका फूल मालाओं से वेलकम किया गया। इसका वीडियो खुद बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस बीच श्रीलंका की ओर से अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा। भारतीय टीम अब गॉल पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। टीम 12 अगस्त की शाम को वहां पहुंची और उसके कुछ ही देर बाद कुछ खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच खास बात ये रही कि सभी की नजर इस बात पर है कि यहां की पिच कैसी होगी। दरअसल श्रीलंका की पिच स्पिनर्स की मददगार मानी जाती है। अगर ऐसा ही कुछ इस बार भी होगा तो टीम की कोशिश होगी कि अपने स्पिनर्स को इसके लिए तैयार रखा जाए। भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में पिछले कुछ वक्त से संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर स्पिनर्स को खेलने में अब वो बात नहीं दिख हरी है, जो पहले हुआ करती थी। टीम कम से कम भारत में अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाती है। इस बार श्रीलंका की टीम में प्रभात जयसूर्या जैसे गेंदबाज हैं, जो निश्चित तौर पर टीम इंडिया के लिए परेशान का सबब बन सकते हैं। हालांकि अभी मैच में दो दिन का वक्त और इस दौरान पिच पर नजर रखने के साथ साथ अपनी तैयारी को भी पुख्ता करने का मौका होगा।

श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने भारतीय टीम को चेतावनी दी

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में 15 अगस्त से खेला जाना है। श्रीलंका को पता है कि गॉल टेस्ट की पहली सुबह अच्छी दिखने वाली पिच तीसरे दिन से बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। उन्हें पता है कि जब पिच रफ हो जाती है, तो बल्लेबाज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अटैक करना है, डिफेंड करना है या बस टिके रहना है। वे यह भी जानते हैं कि भारत को हाल ही में स्पिन के खिलाफ काफी परेशानियां हुई हैं, पिछले दो सालों में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज हारी हैं। इसी को देखते हुए श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने गॉल टेस्ट से पहले चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा पलड़ा भारी है। डी सिल्वा ने शनिवार को गॉल में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से पहले टीओआई से बातचीत में कहा कि टीम इंडिया अपने घर में (न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ) दो सीरीज टर्निंग विकेट पर हारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे टर्निंग विकेट पर खेलना भूल गए हैं। वे निश्चित रूप से वापसी करने के लिए बेचैन होंगे। श्रीलंका की स्ट्रैटेजी भारत को टेस्ट में अंदर तक खींचने की होगी, सरफेस को पुराना होने देना होगा, स्पिनरों को सवाल तय करने देना होगा और देखना होगा कि जवाब किसके पास हैं। डी सिल्वा ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट आसान नहीं है। अगर हम मैच को चौथे और पांचवें दिन तक ले जा सकते हैं, तो हमारे पास उन्हें हराने के ज्यादा मौके होंगे। मुझे उम्मीद है कि हम उनके लिए इसे जितना हो सके उतना मुश्किल बना देंगे और वे सीरीज के दौरान दबाव में रहेंगे।

राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

नाइजीरिया के लागोस में चल रही राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया। एक ही दिन में पांच पदक मिलने के बाद भारत का कुल पदक आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। इसमें आठ स्वर्ण, सात रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने दिन की शुरुआत वरिष्ठ महिला फॉयल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के साथ की। कनागलक्ष्मी ने पूरे मुकाबले में धैर्य और सटीकता के साथ खेलते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी साथी खिलाड़ी जॉयस अशिता ने भी मजबूत प्रदर्शन किया और रजत पदक हासिल किया। इस तरह इस स्पर्धा में भारत ने पहले और दूसरे दोनों स्थानों पर कब्जा कर लिया। मौजूद जानकारी के अनुसार, महिला फॉयल के पदक मुकाबलों में इंग्लैंड की जॉर्जिया ग्रीन और एमिली गुडचाइल्ड ने कांस्य पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और प्रतियोगिता में देश के लिए एक और बड़ी सफलता हासिल की। इसके बाद वरिष्ठ पुरुष एपी स्पर्धा में राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन ने भारत को दिन का दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। शेरजिन ने पूरे मुकाबले में आक्रामक और नियंत्रित खेल दिखाया। फाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर पीटर को हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। क्रूगर को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुष एपी में वेल्स के बर्कहार्ट मार्क और दक्षिण अफ्रीका के लोसेव्स्की सर्गेई ने कांस्य पदक साझा किए। शेरजिन की जीत ने प्रतियोगिता में भारत की पदक तालिका को और मजबूत किया है। गौरतलब है कि दिन का तीसरा स्वर्ण पदक वरिष्ठ पुरुष साबर स्पर्धा में सिंह करण सिंह ने जीता। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के शिम योन्गी के खिलाफ शानदार मुकाबला खेला और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शिम योन्गी को रजत पदक मिला। इस जीत के साथ भारत ने तीसरे दिन तीन अलग-अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए।

वायरल हो रही ये मिस्ट्री गर्ल

ट्रंप को जगाने वाली खास लड़की

ये सारी अजीबोगरीब अफवाहें तब शुरू हुईं जब 10 अगस्त को ओवल ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप के अपनी आंखें खुली रखने में असमर्थ दिखने का एक वीडियो वायरल हुआ.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को जगाने के लिए महिला को काम पर रखा हैं? ऑनलाइन ऐसी अफवाहें तेजी से फैल रही हैं. इन दिनों तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला ट्रंप के पीछे खड़ी नजर आ रही है. कहा जा रहा है कि इस 'रहस्यमयी' को ट्रंप को नींद से जगाने के लिए काम पर रखा गया है. उसके पास ऐसा करने के लिए एक विशेष 'बजर' भी है. डोनाल्ड ट्रंप काम पर ऊंघते रहने की वजह से ऑनलाइन मजाक के पात्र बन गए हैं. इससे पहले वे वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति बिडेन की कथित सुस्ती का नियमित रूप से मजाक उड़ाते रहे थे और उन्हें बार-बार 'स्लीपी जो' कहकर पुकारते थे.सोशल मीडिया पर एक नई थ्योरी तेजी से फैल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक विशेष कर्मचारी को नियुक्त किया है. इस महिला स्टाफ का काम मीटिंग्स में ट्रंप को झपकी आने पर जगाने का है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, कई ऑनलाइन यूजर्स का दावा है कि उस कर्मचारी के पास एक 'बजर' है, जिसे वह राष्ट्रपति को नींद आने पर दबा देती है.ये सारी अजीबोगरीब अफवाहें तब शुरू हुईं जब 10 अगस्त को ओवल ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप के अपनी आंखें खुली रखने में असमर्थ दिखने का एक वीडियो वायरल हुआ. तेज नजर वाले दर्शकों ने तब गौर किया कि जब भी प्रेसिडेंट को नींद आने लगती थी, तो उनके पीछे खड़ी एक महिला जाहिर तौर पर अपना पेट दबाती थी. इसके बाद ट्रंप की आंखें खुल जाती थीं.

किस तरह की थ्योरी ऑनलाइन हो रही वायरल

यूजर्स ने यह अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं. उस मिस्ट्री महिला के पास एक रहस्यमयी बजर है. इस महिला को इसलिए काम पर रखा गया है कि राष्ट्रपति मीटिंग में पूरी तरह से सो न जाएं. इससे पहले उन्हें जगा दिया जाए.

मुंबई लोकल में टूरिस्ट का हाल बेहाल

मुंबई की लोकल ट्रेन शहर की लाइफलाइन कही जाती है. रोज लाखों लोग इसमें सफर करते हैं और भीड़ के बीच ट्रेन पकड़ना उनके लिए रोजमर्रा की बात है. लेकिन पहली बार मुंबई लोकल में सफर करने वाले किसी शख्स के लिए यह अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है. ऐसा ही एक अनुभव दक्षिण कोरिया से भारत घूमने आए टूरिस्ट सेजिन का रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सेजिन पहली बार मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए ठाणे स्टेशन पहुंचे थे.

भूतिया शहर खरीद जमाया बिजनेस

क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स पूरा का पूरा शहर खरीद ले और फिर उसे दोबारा आबाद करने में जुट जाए? अमेरिका में एक शख्स ने ऐसा ही किया है. उसने एक वीरान पड़े पुराने माइनिंग टाउन को अपनी जिंदगी की कमाई से खरीद लिया. अब वह इस भूतिया शहर की पुरानी इमारतों को संवार रहा है और लोगों को यहां घूमने के लिए बुला रहा है.

यह कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेरो गोर्डो शहर की है. कभी यह इलाका चांदी की खदानों के लिए मशहूर था और यहां हजारों लोग रहते थे. लेकिन समय के साथ यह शहर वीरान हो गया. अब यहां फिर से रौनक लौटाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी

कारोबारी ब्रेंट अंडरवुड. ब्रेंट अंडरवुड ने साल 2018 में अपनी जिंदगी की बचत के करीब 1.4 मिलियन डॉलर खर्च करके सेरो गोर्डो को खरीद लिया था. यह शहर कैलिफोर्निया में लोन पाइन के पास मौजूद है. अंडरवुड को बचपन से ही इतिहास और पुराने वेस्ट की कहानियों में दिलचस्पी थी. उनके मुताबिक, बचपन में वह अपने दादा के साथ गन स्मोक देखा करते थे. पुराने अमेरिकी वेस्ट की कहानियों और उस दौर के जीवन ने उन्हें हमेशा एट्रेक्ट किया. यही शौक बाद में उन्हें सेरो गोर्डो तक ले आया. साल 2020 में वह यहां स्थायी रूप से रहने भी आ गए.

लोगों को क्यों बुला रहे हैं अंडरवुड?

अंडरवुड सेरो गोर्डो को सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाकर नहीं रखना चाहते. वह चाहते हैं कि लोग यहां आएं और अमेरिका के पुराने माइनिंग दौर की कहानी को करीब से देखें. उनका कहना है कि किसी किताब में इतिहास पढ़ना अलग बात है. लेकिन उसी जगह पर खड़े होकर उस इतिहास को महसूस करना बिल्कुल अलग अनुभव है.

बाइक को बना दिया 'नंदी'

सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का अलग-अलग अंदाज देखने को मिलता है. कोई पैदल कांवड़ लेकर जाता है तो कोई अपनी कांवड़ को खास तरीके से सजाता है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

वीडियो में एक कांवड़िया कपल ऐसी मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दे रहा है, जिसे भगवान शिव के वाहन नंदी का रूप दिया गया है. बाइक को देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों नंदी पर सवार होकर यात्रा कर रहे हों. वायरल वीडियो में दिखाई दे रही मोटरसाइकिल का रंग सफेद है और इसे नंदी की तरह सजाया गया है. बाइक के आगे और आसपास इस तरह की

डिजाइन और सजावट की गई है कि दूर से देखने पर यह सामान्य मोटरसाइकिल जैसी नहीं लगती. इसी खास लुक की वजह से सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर भी इस बाइक पर टिक जाती है. बाइक पर एक महिला और एक पुरुष बैठे दिखाई दे रहे हैं. दोनों कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए नजर आते हैं और इसी अनोखे वाहन से सफर करते दिख रहे हैं.

राजकुमार राव की 'प्रहार' की नई रिलीज डेट का ऐलान

16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' की नई रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान हो गया है। पहले यह फिल्म अगस्त महीने की 7 तारीख को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी रिलीज को टाल दिया गया था। अब निर्माताओं ने फैसला किया है कि यह चर्चित बायोपिक 16 अक्टूबर 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। हालांकि, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज टालने के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं किया है। जून महीने में जारी किए गए फिल्म के टीजर ने दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दी थी। इस टीजर में भारत के दिग्गज सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के जीवन, उनके लंबे करियर और ऐतिहासिक अदालती लड़ाइयों की एक गंभीर झलक देखने को मिलती है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद पकड़े गए खूंखार आतंकी अजमल कसाब के हाई-प्रोफाइल केस पर केंद्रित नजर आती है। यह मुकदमा भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास के सबसे बड़े पड़ावों में से एक माना जाता है, और टीज़र में अदालती कार्यवाही के उसी तनाव और गंभीरता को बखूबी दर्शाया गया है। फिल्म में राजकुमार राव मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वकील उज्ज्वल निकम के हाव-भाव से लेकर उनके मराठी बोलने के अंदाज को बहुत बारीकी से पकड़ा है। टीज़र में कई भावनात्मक और तीखी अदालती बहसों के दृश्य शामिल हैं, जहां राजकुमार राव का संतुलित अभिनय और फिल्म के दमदार संवाद माहौल को बेहद गंभीर और प्रभावशाली बनाते हैं। खुद असली उज्ज्वल निकम ने भी अभिनेता के काम की सराहना की है। उनका कहना है कि राजकुमार राव ने एक शानदार प्रदर्शन किया है और निर्देशक अविनाश अरुण का काम बेहद प्रभावित करने वाला है। यह बॉलीवुड फिल्म सिर्फ कोर्टरूम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उज्ज्वल निकम के व्यक्तिगत जीवन के उन पहलुओं को भी सामने लाती है जिनसे दुनिया अब तक अनजान थी। इसमें उनके एक पति और पिता के रूप में बिताए जीवन को भी दिखाया गया है। इस बारे में बात करते हुए उज्ज्वल निकम ने बताया कि लोग अक्सर सिर्फ अदालती फैसलों को याद रखते हैं, लेकिन उन फैसलों से पहले वाली रातों के संघर्ष को कोई नहीं जानता। 'प्रहार' उसी अनदेखे पहलू को बड़े पर्दे पर लाने का काम करती है जिसे किसी अखबार की हेडलाइन में जगह नहीं मिली। 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' का निर्देशन अविनाश अरुण ढवरे ने किया है, जिन्होंने कहानी को काफी व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण दिया है। दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में राजकुमार राव के अलावा वामिका गब्बी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

नाम की गलती से लखनऊ के सिपाही को 166 दिन जेल, 1998 में मर चुका था असली आरोपी

सिर्फ नाम एक होने की वजह से लखनऊ के सिपाही अखिलेश त्रिपाठी को राजस्थान पुलिस ने पुराने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया।जिस आरोपी के खिलाफ 1998 में वारंट जारी हुआ था, उसकी उसी साल मौत हो चुकी थी, फिर भी पहचान की पुष्टि किए बिना कार्रवाई हुई।

राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक मामला सामने आया है, जहां सिर्फ नाम एक होने की वजह से लखनऊ में तैनात सिपाही अखिलेश त्रिपाठी को 166 दिन जेल में बिताने पड़े। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ करीब 28 साल पहले गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, उसकी 1998 में ही मौत हो चुकी थी। इसके बावजूद पहचान की सही तस्दीक किए बिना पुलिस ने लखनऊ के रहने वाले सिपाही अखिलेश त्रिपाठी को उसी आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया। मामला 15 फरवरी 2026 का है। मूल रूप से अंबेडकरनगर के रहने वाले और लखनऊ में पुलिसकर्मी के तौर पर तैनात अखिलेश त्रिपाठी गोमतीनगर के ग्वारी गांव में अपने दो बेटों के साथ बाहर निकले थे। इसी दौरान एक एसयूवी उनके पास आकर रुकी और उसमें सवार लोगों ने उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया। घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास के लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया। बाद में परिवार की सूचना पर गोमतीनगर पुलिस सक्रिय हुई। शुरुआती तौर पर स्थानीय पुलिस को मामला अपहरण का लगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और गाड़ी की तलाश शुरू हुई। कुछ समय बाद पता चला कि अखिलेश को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक, सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी थाने में वर्ष 1998 के एक धोखाधड़ी के मामले में अखिलेश त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। इसी मामले में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था और उस पर इनाम भी घोषित बताया गया था। राजस्थान पुलिस ने तकनीकी जानकारी के आधार पर लखनऊ में रहने वाले सिपाही अखिलेश त्रिपाठी तक पहुंच बनाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिपाही ने मौके पर ही पुलिस को बताया कि पहचान में गलती हुई है और उनका इस पुराने मामले से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उनकी बात पर भरोसा नहीं किया गया और उन्हें राजस्थान ले जाया गया। मामले की सबसे बड़ी चूक यहीं सामने आती है। जिस अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ पुराना मामला दर्ज था, वह लखनऊ के अलीगंज इलाके में रहता था और मूल रूप से देवरिया का निवासी बताया गया था। उसके नाम से एक फर्म भी पंजीकृत थी, जिसके जरिए धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उस व्यक्ति की 17 सितंबर 1998 को ही मौत हो चुकी थी। यानी जिस आरोपी को लेकर पुलिस करीब ढाई दशक बाद तलाश कर रही थी, वह गिरफ्तारी के समय जीवित ही नहीं था। मामले में एक और अहम सवाल पहचान को लेकर उठता है। गिरफ्तारी वारंट में आरोपी के पिता का नाम विश्वनाथ दर्ज बताया गया था, जबकि गिरफ्तार किए गए सिपाही के पिता का नाम अलग था। इसके बावजूद पुलिस ने पहचान की पर्याप्त पुष्टि किए बिना कार्रवाई कर दी। अदालत में भी सिपाही की ओर से यही दलील दी गई कि वारंट में दर्ज व्यक्ति और वह खुद अलग-अलग हैं। बाद में पुलिस की ओर से भी यह स्वीकार किया गया कि सही पहचान की पुष्टि नहीं होने के कारण गिरफ्तारी हुई। मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने रिकॉर्ड और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी वारंट और सिपाही के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। अदालत ने पुलिस को भविष्य में ऐसी कार्रवाई करते समय पहचान की पर्याप्त जांच-पड़ताल करने की जरूरत बताई।

लखनऊ के बंथरा में स्कूली वैन रोककर हमला, चालक-बेटे समेत तीन से मारपीट

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी के बंथरा इलाके में दिनदहाड़े स्कूली वैन चालक और उसके बेटे पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि थार, स्कॉर्पियो समेत कई गाड़ियों से पहुंचे लोगों ने पहले वैन रुकवाई और फिर चालक, उसके बेटे व एक अन्य युवक के साथ मारपीट की। हमले में एक युवक धारदार हथियार लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बंथरा गांव निवासी छोटे लाल यादव स्कूली वैन चलाते हैं। उनकी ओर से दर्ज कराई गई तहरीर के मुताबिक, 5 अगस्त की सुबह करीब 11:30 बजे वह बच्चों को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी वैन को रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी थार, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो-एन और एक्सयूवी-300 जैसी गाड़ियों से पहुंचे थे। वैन रुकवाने के बाद उन्होंने छोटे लाल यादव, उनके बेटे आदर्श यादव और चालक गोविंद रावत के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमले के दौरान धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे आदर्श यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। छोटे लाल यादव की तहरीर पर पुलिस ने लकी यादव, अंशुमान सिंह, आकाश सिंह, हिमांशु सिंह, रजत सिंह और 12 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महिलाओं के लिए प्रस्तावित 50 हजार रुपये पर डिंपल यादव ने तीखा हमला बोला

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की महिलाओं के लिए प्रस्तावित 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता योजना ने विपक्ष को सक्रिय कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने भी इस योजना पर तीखा तंज कसा है। हालांकि इस योजना को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, सिर्फ चर्चा हो रही है।प्रस्तावित योजना के मुताबिक, महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है। इसमें चुनाव से पहले 20 हजार रुपये की पहली किस्त दिए जाने की चर्चा है, जबकि बाकी राशि 10-10 हजार की तीन किस्तों में भाजपा सरकार बनने पर दी जा सकती है। पात्रता में एससी-एसटी, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में सालाना आय 12 लाख तक वाले परिवारों को भी शामिल करने की बात कही गई है। उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना बताया जा रहा है। इस चर्चा के बीच डिंपल यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी योजना की चर्चा सुनने को मिल रही है। बिहार और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस तरह की स्थिति के लिए तैयार है, लेकिन वह इसका स्वागत नहीं

करतीं। यानी चुनाव पूर्व नकदी हस्तांतरण की रणनीति को सपा नकार रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी योजना पर निशाना साधा था। उन्होंने इसे भाजपा की पाप की कमाई करार दिया और कहा कि यूपी की धर्मभीरु महिलाएं कभी यह पैसा नहीं लेंगी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछले 10 साल में महिलाओं को सालाना 50 हजार दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया। उनके अनुसार, अब सिर्फ 20 हजार का जुमला परोसा जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को नारी समृद्धि सम्मान योजना के तहत सालाना 40 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी।

एकेटीयू से जुड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए एक और विशेष चरण की काउंसिलिंग

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

प्रदेश के इंजीनियरिंग संस्थानों में सीटें भरने को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से जुड़े संस्थानों में प्रवेश की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। ऐसे में विश्वविद्यालय अब एक और विशेष चरण की काउंसिलिंग करेगा। अभी प्रवेश के लिए लगभग 74 हजार सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय की ओर से पांच चरण की प्रवेश काउंसिलिंग से 25 हजार प्रवेश हुए हैं। जबकि अभी छठें चरण की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इसमें 30 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 22 हजार से ज्यादा छात्रों ने चॉइस भरी है। इस चरण में चॉइस फिलिंग 16 अगस्त तक चलेगी। जबकि सीट एलॉटमेंट 18 को और फिजिकल रिपोर्टिंग 19 से 21 अगस्त तक होगी। इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने 7वें चरण की प्रवेश काउंसिलिंग का भी कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 19 से 23 अगस्त तक होंगे। फीस जमा 19 से 26 अगस्त तक होंगे। चॉइस फिलिंग 23 से 26 अगस्त तक और सीट एलॉटमेंट 27 अगस्त को होगा। वहीं फिजिकल रिपोर्टिंग 29 से 31 अगस्त तक होगी। इस चरण में भी जेईई, सीयूईटी यूजी और उसके बाद 12वीं पास छात्रों को सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा। एकेटीयू कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से प्रवेश के लिए 15 सितंबर तक अनुमति मिली है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय ने छात्रों को एक और प्रवेश का मौका देने का निर्णय लिया है। इन दो विशेष चरणों में अपेक्षित संख्या में प्रवेश होंगे। साथ ही छात्रों को भी बेहतर प्रवेश का विकल्प मिलेगा। विश्वविद्यालय ने 7वें चरण की काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

पुलिसकर्मियों को योगी सरकार 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

यूपी के प्रयागराज में जनवरी-फरवरी में आयोजित महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए यूपी सरकार पुलिसकर्मियों को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दावा किया गया था कि 45 दिनों तक चले महाकुंभ में 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। आयोजन की समाप्ति को लेकर तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा था कि 45 दिनों में प्रयागराज में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, हमने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और तकनीकी दृष्टि से एक अभूतपूर्व मॉडल प्रस्तुत किया। हमने भीड़ नियंत्रण और निगरानी के लिए विश्वस्तरीय तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया है। सभी एजेंसियों के सहयोग से हम अभूतपूर्व प्रदर्शन करने में सफल रहे। महाकुंभ बिना किसी बड़ी त्रासदी के संपन्न हुआ। हमने रेलवे के साथ तालमेल बनाकर काम किया। स्नान के दिनों में 5 लाख से अधिक लोगों ने रेल सेवाओं का उपयोग किया जबकि अन्य दिनों में यह संख्या 3-4 लाख रही। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का एलान किया था।

उन्नाव में पांच किमी लंबी तिरंगा यात्रा, युवाओं ने दिखाया जबरदस्त उत्साह

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

स्वतंत्रता दिवस से पहले गुरुवार शाम उन्नाव शहर और गंगाघाट में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। शाम करीब 5:30 बजे हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से वातावरण गूंज उठा। ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच निकली इन यात्राओं में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुछ स्थानों पर बुलडोजर पर चढ़कर पुष्पों की वर्षा भी की गई। उन्नाव शहर में नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के नेतृत्व में लगभग पांच किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर नॉर्मल स्कूल मैदान तक पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीत गाए और नारे लगाए। ढोल-नगाड़ों की धुन पर युवाओं ने विशेष उत्साह दिखाया, और आतिशबाजी भी की गई। यात्रा में उमड़ी भीड़ ने आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भानु मिश्रा ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य उन्नाव के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र और मातृभूमि से जोड़ना है। उन्होंने जनता से मिले समर्थन और स्नेह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु मिश्रा ने कहा कि कम समय की सूचना पर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यात्रा में शामिल होना प्रशंसनीय है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत संपर्क न होने के बावजूद प्रतिनिधियों के

माध्यम से सूचना मिलने पर भी लोग पहुंचे। उन्होंने युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना के लगातार मजबूत होने पर जोर दिया और कहा कि युवा राष्ट्र के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उधर, गंगाघाट नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका अध्यक्ष कौमुदी पाण्डेय के नेतृत्व और अधिशासी अधिकारी डॉ. राजेश कुमार के मार्गदर्शन में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ पालिका कार्यालय से हुआ। इसमें नगर पालिका के सम्मानित सदस्य, कर्मचारी और प्रबुद्धजन शामिल हुए। तिरंगा यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, निषाद मार्केट, सरस्वती टॉकीज, जूडियो और श्री दुर्गा मंदिर पहुंची। इसके बाद यात्रा मुख्य मार्ग से वापस नगर पालिका कार्यालय पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। यात्रा के दौरान लोगों ने पूरे जोश के साथ वंदे मातरम्, भारत माता की जय और अन्य देशभक्ति के नारे लगाए। समापन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष कौमुदी पाण्डेय ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की आन, बान और शान बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पूरे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाने का आह्वान किया।

पुरवा में सीओ ने पुलिस बल के साथ किया पैदल गश्त, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

गुरुवार को क्षेत्राधिकारी पुरवा अरविंद कुमार चौरसिया ने थाना पुरवा पुलिस बल के साथ कस्बे में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस टीम ने बाजार, मुख्य मार्गों और प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया।पैदल गश्त के दौरान क्षेत्राधिकारी ने कस्बे की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही कानून-व्यवस्था की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बनाए रखें और संदिग्ध गतिविधियों अथवा संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।सीओ ने पुलिस कर्मियों से आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने और किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने बाजार एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।पुलिस की पैदल गश्त के दौरान कस्बे के लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा नजर आया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।क्षेत्राधिकारी ने बताया कि कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस की गश्त लगातार जारी रहेगी। उन्होंने पुलिस टीम को क्षेत्र में नियमित भ्रमण करने और अपराध की रोकथाम के लिए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

उन्नाव के चर्चित मतपेटी लूटकांड में 14 को तीन साल कारावास

उन्नाव में साल 2010 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतपेटियां लूटने के चर्चित मामले में गुरुवार शाम गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायालय ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला आसीवन थाना क्षेत्र के कायमपुर निबरवारा प्राथमिक पाठशाला स्थित बूथ संख्या 162 और 163 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव के दौरान कायमपुर निबरवारा प्राथमिक पाठशाला के बूथ संख्या 162 और 163 से मतपेटियां लूट ली गई थीं। घटना के बाद आसीवन थाना पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में राकेश उर्फ छोटक्के, रामआसरे, रामकिशोर, सरोज, युदरेश, चंद्रभूषण, दिनेश पाल, मान सिंह, बब्लू पाल, सुरेश, दिनेश सिंह, रामू सिंह, राजेंद्र सिंह और खलेपुर समेत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बाद में सभी जमानत पर रिहा हो गए थे। मामले की सुनवाई लंबे समय तक गैंगस्टर एक्ट न्यायालय में चली। इस दौरान दो आरोपी सर्वजीत और शिवदत्त की मौत हो गई। दोनों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई समाप्त कर दी गई। गुरुवार को विशेष न्यायालय में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अलंकार त्रिवेदी और विश्वास त्रिपाठी ने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार यादव ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

रेल मंत्री से मिले साक्षी महाराज, उन्नाव में रेल सुविधाओं के विस्तार की उठाई मांग

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के सांसद आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी साक्षी महाराज ने बुधवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार, बंद यात्री ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करने और लंबे समय से लंबित रेलवे कार्यों को गति देने की मांग रखी। सांसद ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी सीधे तौर पर दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों की जरूरत से जुड़ी है। सांसद ने मुलाकात के दौरान कोरोना काल में बंद हुई पैसेंजर ट्रेनों को फिर से चलाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद कई यात्री ट्रेनों का संचालन अभी तक पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाया है। इससे उन्नाव और आसपास के क्षेत्रों से रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार नई और विशेष ट्रेनों के संचालन की मांग भी रेल मंत्री के सामने रखी। साक्षी महाराज ने ऐतिहासिक बैसवारा हाल्ट रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं का विस्तार करने की मांग की। सांसद ने कहा कि क्षेत्र में यात्री संख्या और जरूरतों को देखते हुए स्टेशन का विकास किया जाना आवश्यक है। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर मूलभूत यात्री सुविधाएं बेहतर करने और स्टेशन परिसर को व्यवस्थित एवं आधुनिक बनाने की मांग रखी। इसके साथ ही उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की जरूरत के अनुसार सुविधाओं के विस्तार का आग्रह किया।

गंगा में मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसा मगरमच्छ

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में गंगा नदी में मछली पकड़ने के दौरान एक मगरमच्छ जाल में फंस गया। यह घटना आनंद घाट के पास हुई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मछुआरों ने बताया कि वे आनंद घाट के पास गंगा में मछली पकड़ने के लिए जाल लगाए हुए थे। जब उन्होंने जाल खींचा, तो उन्हें उसमें मछलियों के साथ किसी बड़ी चीज के फंसे होने का एहसास हुआ। जाल को बाहर निकालने पर उसमें एक मगरमच्छ फंसा हुआ मिला। मगरमच्छ को जाल में फंसा देखकर मछुआरे तुरंत उससे दूर हट गए और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मगरमच्छ को देखने के लिए मौके पर पहुंच गए। लोगों ने दूर से मगरमच्छ का वीडियो बनाया, जो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद आसपास के अन्य घाटों पर भी मगरमच्छ की मौजूदगी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। गंगा नदी में मगरमच्छ मिलने की इस घटना से मछुआरों और नदी किनारे रहने वाले लोगों में भय का माहौल है। मछुआरों का कहना है कि उन्हें अब मछली पकड़ते समय अधिक सावधानी बरतनी पड़ रही है। लोगों ने वन विभाग से नदी में निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

उन्नाव की ओम फार्मा में एंटी नारकोटिक्स टीम की छापेमारी, 8 घंटे चली जांच

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के नेहरूबाग इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ओम फार्मा पर बुधवार दोपहर एंटी नारकोटिक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई कंपनी में नशीले पदार्थों से संबंधित सामग्री के उत्पादन की शिकायत मिलने के बाद की गई। लखनऊ एएटीएफ यूनिट की 8 सदस्यीय टीम ने लगभग 8 घंटे तक जांच की। गुरुवार को सैम्पल जांच के लिए भेजा है। लखनऊ एएटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर सूरज के नेतृत्व में टीम ने कंपनी परिसर में उत्पादन प्रक्रिया, स्टॉक, कच्चे माल और तैयार सामग्री से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की। जांच के दौरान कंपनी में विजयावटी (भांग) बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई। टीम ने कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों से भी पूछताछ की। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, तैयार उत्पाद और उनके रखरखाव से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई। टीम ने मौके से कुछ सामग्री के सैंपल लिए, जिन्हें गुरुवार को जांच के लिए भेजा गया है। छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। मगरवारा चौकी प्रभारी रवि पांडे के साथ भारी पुलिस बल कंपनी परिसर में मौजूद था। सुरक्षा व्यवस्था के बीच एंटी नारकोटिक्स टीम ने कंपनी के विभिन्न हिस्सों में जांच की। इस अचानक हुई कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास की इकाइयों में भी हलचल बढ़ गई। आठ घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों और सामग्री की बारीकी से जांच की गई। हालांकि, छापेमारी में किसी प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी या शिकायत की पुष्टि को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। अधिकारियों के अनुसार, जांच और सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

यूपी में 7 PCS अफसरों का तबादला लखनऊ समेत कई जिलों में बदली प्रशासनिक जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए सात PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं।तबादला सूची में लखनऊ, बलरामपुर, बांदा, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर और आजमगढ़ के अधिकारी शामिल हैं।कई अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि नगर मजिस्ट्रेट और ADM स्तर पर भी बदलाव हुआ है।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने गुरुवार को सात PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती मिली है। तबादला सूची में लखनऊ के साथ-साथ बलरामपुर, बांदा, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के अधिकारी शामिल हैं। प्रशासनिक फेरबदल के तहत अधिकारियों को तत्काल नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के इस कदम से कई जिलों में प्रशासनिक कामकाज का स्वरूप बदलेगा। खास तौर पर नगर मजिस्ट्रेट और अपर जिलाधिकारी स्तर पर हुए बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तबादला सूची में सबसे प्रमुख बदलाव बलरामपुर की अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योति राय का है। उन्हें पदोन्नति देते हुए आजमगढ़ मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी के साथ उनके प्रशासनिक दायित्व का दायरा भी बढ़ गया है। आजमगढ़ मंडल में राजस्व एवं प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी में उनकी भूमिका अहम होगी। वहीं, बांदा के नगर मजिस्ट्रेट संदीप केला को स्थानांतरित कर बलरामपुर का अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बनाया गया है। इस बदलाव के बाद बलरामपुर में राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी। तबादला सूची में बुलंदशहर के उपजिलाधिकारी दिनेश चंद्र को पदोन्नति के बाद बांदा का नया नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें शहरी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर मजिस्ट्रेट के तौर पर कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना उनके प्रमुख दायित्वों में शामिल होगा। इसी क्रम में चंदौली की एसडीएम दिव्या ओझा को स्थानांतरित कर बरेली में अपर जिलाधिकारी न्यायिक की जिम्मेदारी दी गई है। नई तैनाती के साथ उन्हें न्यायिक एवं प्रशासनिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व संभालना होगा।प्रशासनिक फेरबदल में प्रयागराज और गोरखपुर के नगर मजिस्ट्रेटों की भी अदला-बदली की गई है। प्रयागराज के नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को स्थानांतरित कर गोरखपुर का नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वहीं गोरखपुर के नगर मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव को नई जिम्मेदारी देते हुए प्रयागराज का नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। दोनों शहर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र हैं। ऐसे में नगर मजिस्ट्रेट स्तर पर हुए इस बदलाव को स्थानीय प्रशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों अधिकारियों को अपने-अपने नए कार्यक्षेत्र में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। तबादला सूची में राजधानी लखनऊ से जुड़ा महत्वपूर्ण बदलाव निधि पांडेय का है। जन भवन लखनऊ में कम्पट्रोलर के पद पर तैनात निधि पांडेय को अब लखनऊ का उपजिलाधिकारी (SDM) नियुक्त किया गया है। उनकी नई तैनाती के बाद राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

मायावती ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा को पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया

बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण अनंत कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया है। अनंत कुमार मिश्रा को 'उंटू मिश्रा' के नाम से भी जाना जाता है और वो उत्तर प्रदेश में BSP सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। मायावती ने कहा कि वैसे भी, अब जबकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमा गया है, संदेश और अपील यही है कि पार्टी के सभी स्तरों पर लोग विरोधियों की हर तरह की चालों—जैसे प्रलोभन, रिश्वत, सजा, फूट डालना वगैरह—से सावधान रहें और पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ, तन-मन से BSP के अंबेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा चुनावों में सफल बनाने में जुट जाएं। गौरतलब है कि मायावती ने इससे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ के साथ-साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पार्टी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोपों में पार्टी से निकाल दिया था। उत्तर प्रदेश में BSP सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपनी पिछली भूमिका को देखते हुए, अनंत कुमार मिश्रा को पार्टी से निकालना एक अहम संगठनात्मक घटनाक्रम है। BSP का मुख्य मकसद दलितों, पिछड़े वर्गों और समाज के हाशिए पर मौजूद अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करना है और वह अपने राजनीतिक संदेशों में अक्सर डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सिद्धांतों और विरासत का ज़िक्र करती है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ ही, मायावती का बयान पार्टी में अनुशासन को मज़बूत करने और अपने कार्यकर्ताओं को लुभाने या बांटने की किसी भी कोशिश का मुक़ाबला करने के उनके पक्के इरादे को दिखाता है।

जौहर यूनिवर्सिटी की फिलहाल रोक रहेगी

उत्तर प्रदेश की रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आज (13 अगस्त को) मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद रामपुर डीएम के ध्वस्तीकरण आदेश पर मंडलायुक्त की तरफ से 27 जुलाई को लगाई गई अंतरिम रोक को बरकरार रखा गया है। फिलहाल, जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें बुलडोजर की कार्यवाही से बची रहेंगी। आज भी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने अंतरिम रोक को जारी रखा है। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण मामले में फिलहाल स्टे बरकरार है। जौहर यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता जुनैद एजाज ने बताया कि मंडलायुक्त की तरफ से जो SDM रामपुर से रिपोर्ट मांगी गई थी, अभी वो रिपोर्ट भी नहीं आई है। वहीं, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिवक्ता ने कहा कि आज कुछ बिंदुओं पर बहस हुई, जो रिपोर्ट मंगवाई गई थी वो अधूरी आई थी। इसलिए उसे वापस कर दिया गया है। अभी कोई तारीख नहीं लगी है। गौरतलब है कि ये मामला रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने के प्रपोजल से जुड़ा हुआ है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान ने की थी। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत इन्हें गिराने का ऑर्डर दिया है। अथॉरिटी का आरोप था कि ये इमारतें भवन योजना के मंजूरी के बिना बनाई गई थीं। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह ने 27 जुलाई को गिराने के प्रपोजल पर रोक लगा दी थी। हालांकि, बाद में 3 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान इस अंतरिम सुरक्षा को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उठा चुके हैं। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों के नाम खुला खत लिखा था।

अनिल राजभर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित बताया

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बारिश के बीच अपने समर्थकों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। उनके इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता छात्र-छात्राओं समेत सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला है।तिरंगा यात्रा की समाप्ति के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित बताया है। उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एफसीआरए बिल) के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विदेश से आने वाले फंड पर नकेल कसना चाहती है। ऐसे पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी कार्यों के लिए किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव उस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी देश और समाज का निर्माण नहीं होने देना चाहते। भारत के बाहर बैठे लोग साजिश के तहत भारत में पैसा भेजते हैं और इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही किया जाता है, सरकार उस पैसे पर रोक लगाना चाहती है। अनिल राजभर ने कहा कि एक तरफ सरकार भारत विरोधी ताकतों को ऐसा करने से रोकना चाह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी उस पैसे को भारत लाना चाहते हैं, ताकि उसे पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके।